



NaMo 25 · #25YearsofSeva

44 मंत्रालय · मंत्रालय-दर-मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

पीएम-किसान से ई-नाम तक

7 अक्टूबर 2001 → 7 अक्टूबर 2026 · 25 साल, ज़ीरो ब्रेक · 25YearsofSeva.com · संस्करण 88 · 7 अक्टूबर 2026
हर आँकड़ा तिथि सहित — पूरा रिकॉर्ड वेबसाइट पर।



कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय पीएम-किसान से ई-नाम तक

- 24 फरवरी 2019 से पीएम-किसान की 23 किस्तों में ₹4.46 लाख करोड़ से अधिक सीधे किसानों के खातों में पहुँचे; 20 जून 2026 की 23वीं किस्त 9.44 करोड़ किसानों को मिली, जिनमें 2.18 करोड़ महिला किसान हैं।
- कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का बजट 2013-14 के ₹21,933 करोड़ से बढ़कर 2026-27 में ₹1,30,561 करोड़ हो गया — लगभग छह गुना; कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग सहित मंत्रालय का कुल आवंटन ₹1,40,529 करोड़ है (बजट अनुमान 2026-27)।
- अनाज उत्पादन 2013-14 के 2,650 लाख टन से बढ़कर 2025-26 में रिकॉर्ड 3,765 लाख टन हो गया (तृतीय अग्रिम अनुमान, मई 2026)।
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जिसे गुजरात ने 2003-04 में शुरू किया था, 19 फरवरी 2015 को राष्ट्रीय योजना बनी; 18 फरवरी 2016 से पीएम फसल बीमा योजना लागू है।
- ई-नाम से 1.8 करोड़ से अधिक किसान और 1,656 मंडियाँ जुड़ चुकी हैं (मार्च 2026); 10,000 किसान उत्पादक संगठन बनाने का लक्ष्य पूरा हुआ; किसानों को 45 किलो यूरिया का बैग ₹266.50 में मिलता है और शेष लागत सरकार सब्सिडी से वहन करती है।
- बजट 2018-19 से समर्थन मूल्य (MSP) उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुने पर तय करने का सूत्र लागू है; भारत की पहल पर 2023 अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाया गया और मोटे अनाज को "श्री अन्न" की पहचान मिली।